किए गए है। निर्माण के समय लागू मानदण्डों का स क्वार्टरों में पालन किया गया है। पेशवा रोड फ्लैटों के मामले में भी ऐसा किया गया किंतु संशोधित मानदंड में उपलब्ध संविधित सुविधाएं आबंटियों को पूरी तरह मुहैया नहीं कराई जा सकीं।

(घ) ऐसे क्वार्टरों में आबंटियों के अनुरोध पर आवंटी द्वारा कार्य की अनुमानित लागत के आंशिक भुगतान पर मानदंडों के अनुसार सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं।

सरकारी क्वार्टरों में रह रहे अनधिकृत लोग

3085. **श्री मुनव्वर हसनः क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने 1998 में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को गोल डाकखाना, नई दिल्ली के "जी" प्वाइंट में, जिसमें पहले डाक और तार विभाग के मकान थे, जमीन आवंटित की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त क्वार्टरों में अनधिकृत व्यक्ति रह रहे हैं और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के कपटपूर्ण सहयोग से मुफ्त बिजली और पानी भी प्रयोग में ला रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी; और

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद उक्त जमीन/क्वार्टरों को कब तक अपने कब्जे में लेगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां। इस मंत्रालय ने वर्ष 1996 में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को "जी" प्वाइंट नई दिल्ली में भूमि आबंटित की थी।

(ख) से (घ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

Urban Housing in Assam

3086. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the details of projects/schemes undertaken by Government for development of urban housing in Assam during the preceding three years;

(b) the details of grants allocated for each of these schemes/projects;

(c) the details of achievement levels; and

(d) what are the upcoming projects/ schemes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) to (d) Housing being a State subject, the State Governments are to formulate and implement housing schemes as per their priorities and requirements. Central Government does not undertake any project/scheme for development of urban housing in the States.

However, the Housing & Urban Development Corporation (HUDCO) has provided loan assistance to the State Government for undertaking various housing schemes. Details for the last three year are as given below:

(Rs. in crores)

Year	No. of Scheme	Project cost	Loan Amount	Dwelling units
1996-97	6	41.17	21.04	515
1997-98	5	28.14	16.23	1424
1998-99	9	265.04	172.53	37207

Besides the above, HUDCO has received 16 schemes seeking loan assistance of Rs. 20.92 crores. These are at various stages of sanction.